

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-677 / 2014 / भीलवाड़ा

मै० श्री भीम सिंह कान्हेक्टर, भीलवाड़ा  
22 एमटीएम, आर.के.कॉलोनी, भीलवाड़ा।

...अपीलार्थी

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वर्क्स एंड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा
2. उपायुक्त (अपील्स),  
भीलवाड़ा

...प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.पी.शर्मा

अभिभाषक

श्री आर.के.अजमेरा

उप राजकीय अभिभाषक

...अपीलार्थी की ओर से

...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 22.12.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 42/वेट/13-14 में पारित आदेश दिनांक 21.01.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वर्क्स एंड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2011-12 हेतु पारित आदेश दिनांक 24.05.2013 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम 2003" कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत कायम की गई मांग राशि रु. 22,460/- को विवादित करने पर अपील आंशिक प्रतिप्रेषित व आंशिक अस्वीकार की है जिससे व्यथित होकर व्यवसायी द्वारा अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वर्क्स कान्हेक्टर है। अपीलार्थी का कर निर्धारण वर्ष 2011-12 हेतु सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वर्क्स एंड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा द्वारा आदेश दिनांक 24.05.2013 द्वारा पारित किया गया। इस आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये खरीद में वृद्धि की गई है तथा Exemption Fee आधारित कुल प्राप्तियों में से 25 प्रतिशत मजदूरी राशि की कटौती नहीं की गई है। अपीलीय अधिकारी ने सुनवाई का अवसर दिये बिना खरीद में वृद्धि के बिन्दु पर अपील सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित की है। Exemption Fee आधारित प्राप्तियों में से 25 प्रतिशत मजदूरी राशि कम करने के बिन्दु पर अपील इस

211

लगातार.....2



आधार पर अस्वीकार की है कि Exemption Fee का संदाय कुल सकल प्राप्ति पर देय होता है। अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी के उपरोक्त आदेश के विरुद्ध यह द्वितीय अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की हैं।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से उनके कर सलाहकार ने लिखित बहस प्रस्तुत की। लिखित बहस में कथन किया गया कि विवादित मामला कर निर्धारण वर्ष 2011-12 का है जिसका वर्ष सुनवाई का विशिष्ट नोटिस अब नहीं दिया जा सकता क्योंकि कर निर्धारण की समय सीमा 31.03.2014 को समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। ई.सी. फीस पर किये गये कार्य पर मजदूरी राशि बिलडिंग कार्य होने से 25 प्रतिशत की मजदूरी कम करने के पश्चात् ही ई.सी. फीस आरोपित करनी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय में इन्होंने अपने समर्थन में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत (1999) 114 एसटीसी 265 प्रस्तुत किया है। इन्होंने अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।
5. बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अतः निगरानी खारिज की जावें।
6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार हैं :-
7. अपीलार्थी का अपील में प्रथम मुख्य आधार यह है कि ई.सी. फीस पर किये गये कार्य पर मजदूरी राशि बिलडिंग कार्य होने से 25 प्रतिशत की मजदूरी कम करने के पश्चात् ही ई.सी. फीस आरोपित करनी चाहिए थी। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में उद्धरित न्यायिक दृष्टांत अधोहस्ताक्षरकर्ता के विनम्र मत में इस प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या F.12 (63)/FD/Tax 2005-80 dt. 11-08-2006 में जिन कार्य संविदाओं का उल्लेख सूची में किया जाकर ऑटोमेटिक मुक्ति शुल्क जो विहित किया गया है, वह कुल कार्य संविदा मूल्य (Total value of work contract) पर है जबकि माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष विवादित बिन्दु कर्नाटक राज्य के विक्रय कर अधिनियम, 1957 की धारा 17(6) के प्रावधान जो दिनांक 01.04.1996 से पूर्व में विद्यमान थे, का निर्वचन था, जिसमें सकल पण्यावर्त, जो कार्य संविदा निष्पादन के दौरान के वस्तुओं या अन्य रूप में माल सम्पत्ति के रूप में अन्तरित हुयी हो, का उल्लेख था, परन्तु राज्य सरकार द्वारा जारी ऊपर उद्धरित अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 में विशेष रूप से कुल कार्य संविदा मूल्य (Total value of work contract) पर ऑटोमेटिक मुक्ति शुल्क की दर अधिसूचित की गयी है। इस संबंध में का मूल पठन इस प्रकार है:-

**S.No 2130 : F.12 (63)/FD/Tax 2005-80 dt. 11-08-2006**

In exercise of the powers conferred by section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts from payment of



tax the registered dealers engaged in execution of works contracts leviable on the transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract (s) subject to the following conditions, namely:-

1. That in case of works contracts,

(i) awarded on or after 01.04.2006, the contractor shall apply in form WT-1; and

(ii) where the contractor opted for automatic exemption fee under rule 12 of Rajasthan Sales Tax Rules, 1995 shall apply for exemption under this notification for the remaining part of the contract as on April 1, 2006, in form WT-2.

2. That application shall be submitted [within 60 days] from the date of award of the contract or the date of issue of this notification, whichever is later,

3. That in case of delayed submission of the application, the assessing authority may, after recording reasons for doing so, condone the delay, on payment of a later fee of rupees one thousand for a year or part thereof. [However, delay in case of second year or part thereof can be condoned on payment of a late fee of rupees five thousand and no application shall be entertained after expiry of two year from the date of award of the contracts]

4. That on receipt of the application under clause (1), the assessing authority on being satisfied as to the correctness of the facts mentioned therein, shall issue exemption certificate in form WT-3 appended hereto, in the case of works contracts awarded on or after 1.4.2006 and in form WT-4 appended hereto, in the case of work contracts, where the contractor opted for automatic exemption fee under rule 12 of Rajasthan Sales Tax Rules, 1995 for exemption, for the remaining part of the contract as on 01.04.2006. A copy thereof, shall be sent to the awarder.

5. That such contractor shall pay exemption fee at the rate specified in Column 3 of the list given below in the following manner:-

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts from payment of tax the registered dealers engaged in execution of works contracts leviable on the transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract (s) subject to the following conditions, namely:-

- (x) Where an awarder is a Department of any Government a Corporation, a public undertaking a co-operative society, a local body, a statutory body, an autonomous body, a trust or a private or public limited company, an amount calculated at the rate as specified in column no. 3 of the list given below shall be deducted by such awarder from each bill of payment to made in any manner to such contractor and all the provisions of payment of tax provided in the Act or the rules made there under for works contractors shall mutatis mutandis apply. It case the contractor has laready received some payments for execution of works contact from the awarder before filing application, he shall enclose proof of payment/deduction of notified exemption fee on such payments, along with interest, if any, up to the date of filing of application, under this notification;

SM

लगातार.....4



- (xi) Where the awarder is not covered under sub-clause (i) above, the contractor shall be required to make payment of exemption fee in equal monthly installments in a period not exceeding the period of contract from the date of filing of application. In case the contractor has already received some payments for execution of works contract from the awarder, he shall enclose proof of payment of notified exemption fee on such payments, along with interest up to the date of filling of application, under this notification;
- (xii) The amount already deducted by the awarder in lieu of tax from bills of payments to the dealer before the issuance of this notification shall be adjusted against the exemption fee;

**(6) that the contractor shall not be entitled to claim input tax credit in respect of the goods used in execution of the works contract for which exemption certificate has been granted ;**

(7) that the certificate of exemption shall be liable to be cancelled by the assessing authority retrospectively if it is found that the same has been issued under contravention of the provisions of the Act, rules or notification; and

(8) that the tax collected or charged, if any, by such dealer before the issue of this notification shall be deposited, to the State Government and tax so deposited shall not be refunded or adjusted against the exemption fee.

#### LIST

S.No.	Description of Works Contract	Rate of Exemption Fee % of the total value of the contract
1.	Works Contract relating to buildings, roads, bridges, dams, canals, sewerage system.	1.50%
2.	Works Contract relating to Installation of plants & Machinery including PSPO, water treatment plant, laying of pipe line with material.	2.25%
3.	Any other kind of works contract not covered by S.No. 2 & 3.	3.00%

उपरोक्त विधिक स्थित से स्पष्ट है कि ई.सी. फीस का संदाय संविदा में दर्शाई गई कुल राशि पर होगा तथा संविदा कार्य जिस पर ई.सी. फीस दी गई है, में प्रयुक्त माल के क्रय पर कोई इनपुट टैक्स देय नहीं होगा। इस प्रकार अपील का यह आधार भी स्वीकार योग्य नहीं है।

8. अपील में द्वितीय मुख्य आधार यह है कि विवादित मामला कर निर्धारण वर्ष 2011-12 का है जिसका वर्ष सुनवाई का विशिष्ट नोटिस अब नहीं दिया जा सकता क्योंकि कर निर्धारण की समय सीमा 31.03.2014 को समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। इस न्यायालय के विनम्रमतानुसार समय सीमा 31.03.2014 तक थी तथा कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश इससे पूर्व दिनांक 24.05.2013 को पारित कर दिया है तो इसके पश्चात् प्रकरण विभिन्न स्तरों पर

25/

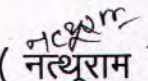


न्यायिक कार्यवाही के दौरान विचाराधीन रहा है तो वह अवधि सीमा की गणना हेतु नहीं मानी जायेगी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण रिमाण्ड किया है तो इस आधार पर कार्यवाही समाप्त नहीं की जा सकती कि प्रकरण में समय सीमा समाप्त हो चुकी है।

9. इस प्रकार प्रकरण में ई.सी. पर किये गये कार्य पर देय कर की गणना कार्य आदेश में दर्शायी गयी राशि के आधार पर ही किया जाने का प्रावधान है तथा इसमें से मजदूरी राशि कम नहीं की जा सकती तथा खरीद में वृद्धि के संबंध में सुनवाई का अवसर देने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसम्मत है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी का निर्णय विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।

  
( नत्थूराम )  
सदस्य